भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1028
सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

नौकरियों का अनुमान

1028. श्री ए. राजा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में युवाओं की बेरोजगारी से निपटने के लिए वार्षिक रूप से सृजित होने वाली नौकरियों की अनुमानित संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष-बार कितने रोजगार सृजित किए गए;

(घ) क्या सरकार को आईआईएम, लखनऊ और सिटी ग्रुप की रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि भारत को वार्षिक रूप से 1.2 करोड़ नौकरियों की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, न्यूनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, 2021-22 और 2022-23 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए सामान्य स्थिति पर कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 52.9% और 56% था, जो यह इंगति करता है कि डब्ल्यूपीआर यानी रोजगार में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति है।

2020-21 से 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति पर देश में, व्यापक उद्योग प्रभाग कामगारों का वितरण प्रतिशत अनुलग्नक में है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम केएलईएमएस डेटा के अनुसार, देश में रोजगार वर्ष 2017-18 में 47.5 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2017-18 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 16.83 करोड़ है।

सभी श्रम बल संकेतक देश में बेहतर रोजगार परिदृश्य का प्रमाण दे रहे हैं और सरकार ने सिटीग्रुप की रिपोर्ट का खंडन किया है कि भारत 7% की विकास दर के साथ भी पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए संघर्ष करेगा।

रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना आदि। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों के विवरण को https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 29.07.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1028 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान देश में, सामान्य स्थिति के आधार पर व्यापक उद्योग प्रभाग द्वारा कामगारों का अनुमानित वितरण (% में)।

क्र.सं.	व्यापक उद्योग प्रभाग	2020-21	2021-22	2022-23
1	कृषि	46.5	45.5	45.8
2	खनन एवं उत्खनन	0.3	0.2	0.3
3	उत्पादन	10.9	11.6	11.4
4	बिजली, पानी, आदि.	0.6	0.6	0.5
5	निर्माण	12.1	12.4	13.0
6	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	12.2	12.1	12.1
7	परिवहन, भंडारण एवं संचार	5.4	5.6	5.4
8	अन्य सेवाएं	12.0	11.6	11.4
	योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई